(ख) क्या चालू पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश के सभी जन-जातीय क्षेत्रों के विकास खंड मुख्यालयों को टेलीफोन सुविधा दे दिये जाने का कोई प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) मध्य प्रदेश के पूर्णतया/आंशिक रूप से पिछड़े 34 जिलों में 5-5 कि०मी० की भुजा के 517 आबादी वाले षटभुजाकार क्षेत्रों में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दूरसंचार सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई गई है । इनमें से 325 षटभुजाकार क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधायें पहले प्रदान कर दी गई हैं ।

(ख) सभी जनजातीय ब्लाक मुख्यालयों में दूरसंचार सुविधायें प्रदान कर दी गई हैं ।

Soviet aid to Power Sector

1964. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether the Soviet Union has offered to provide more aid for power sector in India; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI KALPNATH RAI): (a) and (b) An Inter-Governmental Protocol has recently been signed with the Government of USSR for construction, upto 2000 A.D., of new electric power stations with a total capacity upto 6000 MW, along with the associated transmission systems, with Soviet Assistance. Under the Protocol five power projects, with a total capacity of 3270 MW are to be constructed and synchronised during the Eighth Five Year Plan. A credit Agreement, providing financial assistance of Roubles 400 million for Vindhyachal Super Thermal Power Project Stage-II, has also been concluded with the Government of USSR.

कानपुर में असंतोषजनक टेलीफोन सेवा

1965. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि युवा उद्योग व्यापार मंडल, कानपुर के आह्वान पर कानपुर टेलीफोन्स की कुव्यवस्था के विरोध में 26 सितम्बर, 1988 को टेलीफोन की शव यात्रा निकाली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां, कानपुर में असंतोषजनक टेलीफोन सेवाओं के विरोध में 26 सितम्बर, 1988 को टेलीफोन की शवयात्रा निकाली गई थी ।

(ख) आन्दोलनकारियों से विचार विमर्श करके और एक्सचेंजों में उत्पन्न दोषों की व्यापक जांच करके उन्हें दूर करने जैसे सुधारात्मक कदम उठा कर इस मामले को सुलझा दिया गया था ।

Visit of Deputy Director General of World Intellectual Property Organisation to India

1966. SHRI SHAMIM HASHMI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) how many times Mr. Shahid Ali Khan, Deputy Director General of World Intellectual Property Organisation (WIPO) has visited India during the last six months;

(b) whether it is a fact that he has held discussions with the Senior Officials of the Ministry persuading India to join the Paris Convention; and